सीमेंट की कमी

1520. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्षों में देश को सीमेंट की कमी का सामना करना पड़ेगा, यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ख) इस कमी को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) अनुमानित मांग को ध्यान में रखते हुए, सीमेंट उत्पादन में विकास की पिछली प्रवृत्ति और नयी क्षमताओं के संयोजन हेतु पहले ही से स्वीकृत योजनाएं हैं, आने वाले वर्षों में देश में सीमेंट की कोई खास कमी का अनुमान नहीं है।

(ख) बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सीमेंट उत्पादन अधिकतम करने हेतु किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :

(1) सीमेंट उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है अर्थात् अब नये सीमेंट एकक स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस अथवा विद्यमान एककों के पर्याप्त विस्तार हेतु औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत नहीं है ;

(2) सीमेंट उद्योग को कोयला, रेल वैगन तथा अन्य आधार भूत सहायता की कड़ी निगरानी करना और जहां कहीं आवश्यक हो वहां शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करना तथा

(3) क्षेत्रीय मांग-आपूर्ति असंतुलनों को कम करने के लिए अधिकता वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में सीमेंट पहुंचाना।

Poverty Line in Tamil Nadu

1521. SHRI R. T. GOPALAN: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state ::

(a) the percentage of population living below the poverty line in Tamil Nadu as per the last survey;

(b) to what extent it is more in comparison to other States;

(c) whether any programme is being chalked out to bring them above the poverty line; if so, the details thereof;

(d) whether Government of Tamil Nadu have proposed some measurers in this regard to the Union Government; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) and (b) In 1987-88 the latest year for which information is available, the percentage of people living below poverty line in rural and urban areas of Tamil Nadu and comparative position of other States|Union Territories is given in the statement attached.

(c) Four Centrally-Sponsored|Central Sector schemes for alleviation of poverty in Tamil Nadu are being implemented. These are:—

(i) Integrated Rural Development Programme (IRDP) which provides self-employment in rural areas.

(ii) Jawahar Rozgar Yojana (JRY) which provides wage-employment in rural areas;

(iii) Self-Employment Programme for Urban Poor (SEPUP).

(iv) Nehru Rozgar Yojana (NRY) which provides wage-employment in urban areas.

(d) and (e) No new measures have been proposed in this regard by the Government of Tamil Nadu.